वर्ष : 01 > अंक : 01 | RNi NO RAJHIN26/A8486 | ITIB | Hello@ankitinspiresindia.com | पृष्ठ : 8 > मूल्य: 2.00

इंडिया दैट इज भारत

साप्ताहिक

"INSPIRED INDIA. INFORMED BHARAT."

जयपुर, रविवार, 08 नवंबर 2026

INSIDE PAGE



मिडटर्म में डेमोक्रेट्स ने 40 से ज्यादा सीटें छीनीं, अब हर कानून पर ट्रंप को चाहिए विपक्ष का साथ

पेज @ 2



वायु रक्षा को मज़बूती की तैयारी: 'अनंत शस्त्र' के ₹30,000 करोड़ के सौदे पर मुहर का इंतज़ार

पेज @ 5



क्रिप्टो बाज़ार धड़ाम: बिटकॉइन 6% टूटकर 75,000 डॉलर के पास

पेज @ 6

PM मोदी-राहुल के बीच खुली बहस की चुनौती

BJP ने दिया संसद में चर्चा का जवाब

ITIB डेस्क

नई दिल्ली। हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच खुली बहस की मांग ने भारतीय राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और चुनावी प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर आमने-सामने बैठकर सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दी है। यह विवाद केवल दो नेताओं के बीच बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में राजनीतिक संवाद, संसदीय परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेही से भी जुड़ा है।



राहुल गांधी ने संसद में बहस के प्रस्ताव पर क्या कहा?

अमित शाह की पेशकश के बाद राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी। 4 नवंबर को पंजाब के संगरूर में कांग्रेस की रैली के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार संसद में चर्चा की बात करती है, लेकिन विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता और उनका माइक बंद कर दिया जाता है। उन्होंने सार्वजनिक मंच पर बहस की अपनी चुनौती दोहराई।

राजनीतिक बहस और जवाबदेही का सवाल : भारत में राजनीतिक दल चुनावी रैलियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और संसद के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच सीधी सार्वजनिक बहस की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है।

शेष पेज 7 पर

BJP का पलटवार: संसद में आकर बहस करें राहुल

राहुल गांधी की चुनौती पर 4 नवंबर को BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद में चर्चा से बचते हैं और प्रधानमंत्री के जवाब देने के दौरान सदन से बाहर चले जाते हैं। त्रिवेदी ने 2023 के अविश्वास प्रस्ताव और मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा की कार्यवाही का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता पर सवाल उठाए। इसके बाद 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल में आयोजित BJP की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली में राहुल गांधी को जवाब दिया। शाह ने कहा कि अगर राहुल गांधी वास्तव में बहस करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखें। सरकार SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है। शाह ने राहुल गांधी पर संसद की कार्यवाही बाधित करने और चर्चा के बजाय हंगामा तथा वॉकआउट करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र में बहस का सबसे उपयुक्त मंच है।

E20 पेट्रोल पर राहुल का हमला, बोले...

जनता की गाड़ी से हो रही पेट्रोल चोरी... 31.2% तक एथेनॉल मिलने का दावा



ITIB डेस्क

नई दिल्ली। देश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल में निर्धारित 20% से अधिक एथेनॉल मिलाए जाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और तेल कंपनियों पर निशाना साधा। उन्होंने इसे जनता की गाड़ियों से पेट्रोल चोरी बताते हुए कहा कि उपभोक्ता पेट्रोल की कीमत चुका रहे हैं, लेकिन उन्हें निर्धारित मात्रा से अधिक एथेनॉल दिया जा रहा है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा कर लिखा, 'E20 बना 420- जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी!' उन्होंने कर्नाटक सरकार की ओर से सात जिलों में पेट्रोल के नमूनों की जांच के नतीजों का हवाला दिया। राहुल के मुताबिक, 14 नमूनों में से 11 में एथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक पाई गई। इनमें इंडियन ऑयल के एक नमूने में 31.2% और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नमूने में 30.5% एथेनॉल होने का दावा किया गया।

सात जिलों से लिए गए पेट्रोल के नमूने

कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु में पेट्रोल के नमूने एकत्र किए थे। इनमें IOCL, BPCL, HPCL और निजी कंपनियों के पेट्रोल को शामिल किया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलने से वाहनों का माइलेज प्रभावित हो सकता है और रखरखाव का खर्च बढ़ सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में जवाब मांगा।

तेल कंपनियों ने जांच पर उठाए सवाल

राहुल गांधी के आरोपों के बाद IOCL, BPCL और HPCL ने संयुक्त बयान जारी कर जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कंपनियों का कहना है कि जांच निर्धारित कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं की गई। उनके मुताबिक, देशभर में सप्लाई किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

शेष पेज 7 पर

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

पराली के साथ गाड़ियों के धुएं पर भी उठाए सवाल

ITIB डेस्क. नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि प्रदूषण के लिए केवल पराली जलाने को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वाहनों से निकलने वाला धुआं, ट्रैफिक जाम और स्थानीय प्रदूषण के अन्य स्रोत भी समस्या को गंभीर बना रहे हैं।

शेष पेज 7 पर



भजनलाल सरकार के तीन साल

कितने वादे पूरे, कितनी चुनौतियां बाकी?

ITIB डेस्क

जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 15 दिसंबर 2026 को अपने तीन साल पूरे करने जा रही है। दिसंबर 2023 में सत्ता संभालने के बाद सरकार ने निवेश, बुनियादी ढांचे, पेयजल, ऊर्जा और महिला कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। सरकार का दावा है कि चुनावी घोषणापत्र के करीब 78% वादे पूरे किए जा चुके हैं। वहीं, विपक्ष सरकार के कामकाज और कई बड़ी घोषणाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में तीसरे साल में सरकार के सामने उपलब्धियों को ठोस परिणामों में बदलने की चुनौती है।

राइजिंग राजस्थान से निवेश की उम्मीद: सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में दिसंबर 2024 में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट शामिल है। इसमें करीब 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते (MOU) हुए। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इनमें से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर धरातल पर काम शुरू हो चुका है। हालांकि, MOU और वास्तविक निवेश में अंतर है। इन परियोजनाओं को पूरा कराना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना सरकार की अगली परीक्षा होगी।



जल संकट के समाधान के लिए बड़े समझौते: राजस्थान में पानी की कमी लंबे समय से बड़ी समस्या रही है। सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना यानी रामजल सेतु लिंक परियोजना को आगे बढ़ाया है। करीब 90 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना के पहले चरण से 17 जिलों में लगभग 3.25 करोड़ लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

शेष पेज 7 पर

इंडिया ITIB दैट इज भारत
साप्ताहिक समाचार पत्र

मिडटर्म में डेमोक्रेट्स ने 40 से ज्यादा सीटें छीनीं, अब हर कानून पर ट्रंप को चाहिए विपक्ष का साथ

संसद के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स को बहुमत

ITIB डेस्क

वॉशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिका में 3 नवंबर को हुए मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसद के निचले सदन, हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स, में 40 से ज्यादा सीटें रिपब्लिकन से छीन लीं, और ऊपरी सदन, सीनेट, में भी बहुमत हासिल कर लिया।

अमेरिकी मीडिया के अनुमानों के मुताबिक डेमोक्रेट्स निचले सदन में 254 के आसपास सीटों तक पहुंच रहे हैं। बहुमत के लिए 218 सीटें चाहिए। सबसे अहम बात ये रही कि रिपब्लिकन पार्टी विरोधियों से एक भी सीट नहीं छीन पाई। कुछ सीटों पर अंतिम गिनती अभी जारी है।

ट्रंप ने क्या कहा?: ट्रंप ने माना कि नतीजों से वो 'थोड़े हैरान' हैं। उन्होंने कहा कि वो ख़ुद बैलेट पर होते तो पार्टी भारी जीत हासिल करती। साथ ही उन्होंने ईरान युद्ध के असर की बात मानी, और हार के लिए कुछ उम्मीदवारों और तेल की ऊंची कीमतों को भी जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने नतीजे स्वीकार करने और नई संसद के साथ काम करने की बात कही है। डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ़्रीज़ ने इसे अमेरिकी जनता की 'ज़बरदस्त जीत' बताया।



मिडटर्म क्या होता है?

अमेरिका में राष्ट्रपति चार साल के लिए चुना जाता है। उसके कार्यकाल के बीच, यानी दो साल बाद, संसद के चुनाव होते हैं। इन्हें मिडटर्म कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति के कामकाज पर जनता का फ़ैसला माना जाता है। इतिहास में अक्सर सत्ताधारी पार्टी को मिडटर्म में नुकसान होता रहा है, लेकिन इस बार हार का अंतर बड़ा है।

भारत पर असर: भारत की नज़र तीन बातों पर है

- **टैरिफ़:** फरवरी में तय हुआ भारत-अमेरिका व्यापार ढांचा अब तक पूरा नहीं हुआ है। नई संसद का रुख़ इस पर असर डाल सकता है।
- **तेल:** ईरान युद्ध पर संसद का दबाव बढ़ा तो तेल के दाम पर भी असर पड़ेगा। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 89% कच्चा तेल आयात करता है।

रणनीति: रक्षा और तकनीक में भारत-अमेरिका सहयोग को दोनों दलों का समर्थन रहा है, इसलिए इसमें बड़े बदलाव की उम्मीद कम है।

अब क्या बदलेगा?

अमेरिका में कोई भी नया कानून तभी बनता है जब संसद के दोनों सदन उसे पास करें। अब दोनों जगह विपक्ष का बहुमत है, इसलिए ट्रंप के अगले दो साल के हर बड़े कानूनी फ़ैसले के लिए डेमोक्रेट्स का साथ ज़रूरी होगा। बजट, युद्ध पर ख़र्च और व्यापार नीति जैसे मुद्दों पर अब ट्रंप को विपक्ष से बातचीत करनी होगी। संसद की समितियां सरकार के फ़ैसलों की जांच भी तेज़ कर सकती हैं।

यूरोप@ अर्थव्यवस्था

महंगाई के खिलाफ़ यूरोप सड़कों पर



फ्रांस में 5 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल, जर्मनी और बेल्जियम में झड़पें; सात देशों की यूनियनें 20–22 नवंबर को साझा प्रदर्शन करेंगी

ITIB डेस्क.नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई और सरकारी ख़र्च में कटौती के खिलाफ़ यूरोप के कई देशों में लोग सड़कों पर हैं। यूरोपीय संघ के सांख्यिकी विभाग यूरोस्टैट के मुताबिक सितंबर में EU में सालाना महंगाई दर बढ़कर 3.8% हो गई, जो अगस्त में 3.2% थी।

फ्रांस: छात्रों से मज़दूरों तक: फ्रांस में छात्रों के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन अब देशव्यापी हो गया है। देश के पांच बड़े मज़दूर संगठनों ने वेतन, पेंशन, सरकारी सेवाओं और बजट कटौती के मुद्दे पर 5 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल बुलाई। रेल कर्मचारियों के संगठनों ने भी इसमें शामिल होने का एलान किया। इससे पहले 24 अक्टूबर के प्रदर्शनों में फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक करीब 4 लाख लोग शामिल हुए थे, जबकि यूनियनों ने ये संख्या इससे दोगुनी बताई।

दूसरे देशों में भी उबाल: इटली में महंगाई के खिलाफ़ देशव्यापी हड़ताल हो चुकी है। जर्मनी में 31 अक्टूबर के आसपास हुए प्रदर्शनों में कुछ जगह हिंसा हुई। बेल्जियम के ब्रसेल्स और लीज शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं।

बड़ा साझा प्रदर्शन: फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, यूनान, स्पेन, पुर्तगाल और इटली की यूनियनों ने 20 से 22 नवंबर के बीच साझा प्रदर्शन की घोषणा की है।

यूरोप@युद्ध और कूटनीति

अबू धाबी में रूस-यूक्रेन वार्ता की तैयारी, रिफ़ाइनरी हमलों से भरोसा कमज़ोर



ITIB डेस्क

नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि 10 और 11 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आमने-सामने बैठेंगे। अमेरिका इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा।

अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ ने बताया कि बातचीत युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था, तनाव घटाने, मानवीय मदद और शांति के अगले कदमों पर होगी। अमेरिका की ओर से विटकॉफ़ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के शामिल होने की उम्मीद है। रूस की सरकार ने भी बैठक की पुष्टि की है।

- **यूक्रेन का एजेंडा:** यूक्रेन चाहता है कि इस दौर में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाक़ात की ज़मीन तैयार हो, और कुछ क्षेत्रों में युद्धविराम पर सहमति बने। भरोसे की कमी बातचीत से पहले ही माहौल तनावपूर्ण है। यूक्रेन ने रूस की तेल रिफ़ाइनरियों पर ड्रोन हमले फिर शुरू कर दिए हैं। रूसी शहर यारोस्लाव के गवर्नर के मुताबिक एक हमले में वहां की रिफ़ाइनरी को नुकसान पहुंचा।
- **पहले भी हो चुकी है बात:** इसी साल जनवरी और फरवरी में भी अबू धाबी में तीनों पक्षों की बातचीत हुई थी। तब सबसे बड़ा विवाद रूस की इस मांग पर था कि यूक्रेन डोनबास के बाकी हिस्सों से पीछे हटे। भारत की नज़र: युद्ध थमने से तेल और खाद की वैश्विक कीमतें स्थिर हो सकती हैं। रूस से कच्चे तेल की ख़रीद पर भारत को अमेरिका के रुख़ का भी ध्यान रखना होगा।

एशिया@सुरक्षा

ताइवान के आसपास समुद्री मैपिंग तेज़ कर रहा चीन

ITIB डेस्क. नई दिल्ली। चीन ने ताइवान के आसपास समुद्र की तलहटी का नक्शा बनाने का काम तेज़ कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक इसके लिए दर्जनों सर्वे और रिसर्च जहाज़ लगाए गए हैं।

मैपिंग क्यों अहम?: समुद्र की गहराई, तलहटी की बनावट, पानी का तापमान और धाराओं की जानकारी पनडुब्बियों के लिए बेहद ज़रूरी होती है। इसी से तय होता है कि पनडुब्बी कहां छिप सकती है और दुश्मन की पनडुब्बी को कैसे खोजा जाए। रक्षा विशेषज्ञ ऐसे आंकड़ों को 'युद्ध के मैदान की तैयारी' मानते हैं। यही जानकारी समुद्र के नीचे चलने वाले ड्रोन के लिए भी काम आती है।

बढ़ता तनाव: इसी दौरान चीन के तट रक्षक बल ने ताइवान के पूर्व के समुद्र में गश्त की, जिसे चीन ने 'सामान्य कानूनी गश्त' बताया। ताइवान के तट रक्षक बल ने आरोप लगाया कि दक्षिण चीन सागर में उसके नियंत्रण वाले एक विवादित द्वीप के पास एक चीनी जहाज़ प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस आया।



इंडिया दैट इज भारत
ITIB
साप्ताहिक समाचार पत्र

लगातार सातवें दिन तेज़ी
सेंसेक्स 81,000 और निफ़्टी फिर 25,000 के पार



दो दिन में 3,700 से ज्यादा अंकों की छलांग... सस्ते तेल और विदेशी निवेशकों की ख़रीद से बैंक शेयर चमके, रुपया भी मज़बूत

ITIB डेस्क

नई दिल्ली। शेयर बाज़ार में तेज़ी का सिलसिला 6 नवंबर को लगातार सातवें कारोबारी दिन भी जारी रहा। बीएसई सेंसेक्स 1,700 से ज्यादा अंक यानी करीब 2.17% चढ़कर 81,028 पर बंद हुआ। एनएसई निफ़्टी करीब 2% की बढ़त के साथ एक बार फिर 25,000 के ऊपर पहुंच गया।

इससे एक दिन पहले, 5 नवंबर को सेंसेक्स 2,008 अंक उछला था और उस एक दिन में निवेशकों की संपत्ति करीब 7 लाख करोड़ बढ़ी थी। यानी सिर्फ़ दो कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 3,700 से ज्यादा अंक चढ़ चुका है।

बैंक शेयरों ने संभाली कमान: 6 नवंबर की तेज़ी में सबसे आगे बैंकों के शेयर रहे। हालांकि छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में उतनी तेज़ी नहीं दिखी, और अलग-अलग क्षेत्रों का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। जानकारों के मुताबिक बड़ी कंपनियों में विदेशी निवेशकों की ख़रीद ने इंडेक्स को ऊपर खींचा।

तेल क्यों गिरा?: ईरान और अमेरिका के बीच करीब ढाई सौ दिन से चल रहे टकराव में शांति वार्ता की उम्मीद जगी है। इसी उम्मीद में अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल का मानक ब्रेंट इस हफ़्ते 18% से ज्यादा टूटा, और 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुज़रता है। वहां तनाव घटने की उम्मीद ने तेल बाज़ार से डर का प्रीमियम काफ़ी हद तक हटा दिया।

भारत को सबसे ज्यादा फ़ायदा

भारत अपनी ज़रूरत का करीब 89% कच्चा तेल बाहर से ख़रीदता है। इसलिए तेल के दाम में हर बड़ी गिरावट भारत के लिए सीधी राहत है। तेल सस्ता होने से देश का आयात बिल घटता है, तेल कंपनियों और सरकार पर बोझ कम होता है, और महंगाई पर लगाम लगाने में मदद मिलती है।

विदेशी पैसा लौटा

इस तेज़ी की दूसरी बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की वापसी है। उन्होंने 5 नवंबर को अकेले 14,975 करोड़ के भारतीय शेयर ख़रीदे, और उससे पहले के पांच सत्रों में उनकी कुल ख़रीद 35,000 करोड़ से ज्यादा रही। अमेरिका के मिडटर्म चुनाव के नतीजों के बाद दुनिया भर के निवेशक नई नीतियों का आकलन कर रहे हैं। इस दौर में भारत को तेज़ी से बढ़ती और अपेक्षाकृत स्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है।

रुपया भी चमका

विदेशी पैसे की आवक और सस्ते तेल का असर रुपये पर भी दिखा। 6 नवंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले 56 पैसे मज़बूत होकर करीब 93.9 पर बंद हुआ। बाज़ार के सूत्रों के मुताबिक रिज़र्व बैंक ने रुपये में ज्यादा तेज़ उतार-चढ़ाव रोकने के लिए डॉलर की ख़रीद भी की।

आगे क्या?

सात दिन की लगातार तेज़ी के बाद जानकार कुछ मुनाफ़ावसूली की संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे। उनका मानना है कि आगे बाज़ार की दिशा तीन बातों पर टिकी रहेगी: ईरान वार्ता का नतीजा, कच्चे तेल की कीमत, और विदेशी निवेशकों का रुख़। 8 नवंबर को दिवाली पर होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ बाज़ार नए संवत में प्रवेश करेगा।

- **आपके लिए मतलब:** तेल सस्ता और रुपया मज़बूत बना रहा तो आने वाले महीनों में पेट्रोल-डीज़ल और महंगाई पर राहत की गुंजाइश बनेगी। लेकिन लगातार तेज़ी देखकर जल्दबाज़ी में निवेश न करें। ऊंचे स्तरों पर बाज़ार में उतार-चढ़ाव भी बढ़ता है, इसलिए पैसा हमेशा लंबी अवधि की सोच के साथ लगाएं।

दिवाली पर NSE-BSE में बजेगी ट्रेडिंग की घंटी, 8 नवंबर को मिलेगा शुभ मुहूर्त में निवेश का मौका... जानिए समय और पूरी परंपरा

रविवार को भी खुलेगा शेयर बाजार!

ITIB डेस्क

मुंबई। दिवाली का त्योहार यानी नई उम्मीद, समृद्धि और शुभ शुरुआत। इस मौके पर जहां घरों में मां लक्ष्मी की पूजा होती है, वहीं शेयर बाजार में भी निवेशक शुभ मुहूर्त में कारोबार कर नए संवत की शुरुआत करते हैं। इसी खास परंपरा को मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है। साल 2026 में NSE और BSE रविवार, 8 नवंबर को विशेष ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे। खास बात यह है कि बाजार सामान्य छुट्टी के दिन भी सीमित समय के लिए खुलेगा।

मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा: मुहूर्त ट्रेडिंग भारतीय शेयर बाजार की वर्षों पुरानी परंपरा है। दिवाली के दिन हिंदू कैलेंडर के नए संवत की शुरुआत होती है। निवेशक इस शुभ अवसर पर शेयर खरीदकर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत सकारात्मक सोच और समृद्धि की कामना के साथ करते हैं। इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ संवत 2083 की शुरुआत होगी। कई निवेशक इस दिन प्रतीकात्मक रूप से एक या दो शेयर खरीदते हैं और इसे नए निवेश की शुभ शुरुआत मानते हैं।

क्या मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार चढ़ता है?: मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार में निवेशकों का उत्साह देखने को मिलता है। कई बार इस विशेष सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं, लेकिन हर साल तेजी की कोई गारंटी नहीं होती।



मुहूर्त ट्रेडिंग 2026

- तारीख: 8 नवंबर 2026, रविवार
- प्री-ओपनिंग: दोपहर 2:05 से 2:20 बजे
- सामान्य ट्रेडिंग: दोपहर 2:20 से 3:30 बजे
- एक्सचेंज: NSE और BSE

इस दौरान निवेशक शेयरों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे। हालांकि, यह सामान्य कारोबारी दिन के बजाय विशेष ट्रेडिंग सेशन होगा।

2016 से 2025 तक निफ्टी-50 और सेंसेक्स का प्रदर्शन

पिछले वर्षों के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रों में बाजार के खुलने और बंद होने के स्तर से यह समझा जा सकता है कि इस खास कारोबारी दिन बाजार का रुख कैसा रहा है।

शुभ मुहूर्त में निवेश, लेकिन सोच-समझकर!: मुहूर्त ट्रेडिंग का महत्व धार्मिक आस्था और बाजार की परंपरा से जुड़ा है। लेकिन केवल शुभ समय देखकर किसी शेयर में निवेश करना सही रणनीति नहीं है। निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन और अपने वित्तीय लक्ष्यों को जरूर ध्यान में रखें।

याद रखें: शुभ शुरुआत के साथ सही निवेश रणनीति भी जरूरी है।

त्योहारी मांग का असर नवंबर में भी दिखने की उम्मीद

अक्टूबर में GST से ₹2.31 लाख करोड़, 22.9% की बढ़त



ITIB डेस्क

नई दिल्ली। त्योहारी सीज़न ने सरकार का ख़ज़ाना भरा है। अक्टूबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर (GST) से करीब 2.31 लाख करोड़ का सकल संग्रह हुआ। ये पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 22.9% ज्यादा है। आंकड़े 1 नवंबर को जारी किए गए। रिफ़ंड घटाने के बाद शुद्ध संग्रह करीब 2.03 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल से करीब 25.6% ज्यादा है।

कहां से आई बढ़त?: देश के भीतर हुए लेनदेन से कर संग्रह करीब 15.8% बढ़ा। दशहरा और दिवाली के सीज़न में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों और रोज़मर्रा के सामान की ख़रीदारी बढ़ने से ये उछाल आया।

सबसे तेज़ बढ़त आयात से जुड़े कर में दिखी। ये करीब 42.2% बढ़कर 72,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया।

- **एक सावधानी:** कुछ जानकारों का मानना है कि आयात से जुड़े कर में इस उछाल का एक हिस्सा कीमतों के असर से भी है। यानी आयात होने वाली चीज़ें महंगी होने से कर ज्यादा जमा हुआ, सिर्फ़ ज्यादा मात्रा में आयात होने से नहीं। इसलिए पूरी तस्वीर अगले कुछ महीनों के आंकड़ों से ही साफ़ होगी।



इंडिया ITIB दैट इज भारत
साप्ताहिक समाचार पत्र

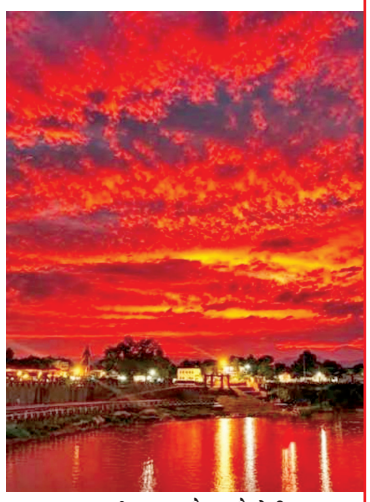
जयपुर, रविवार, 08 नवंबर 2026

संपादकीय

किरंदुल का लाल आसमान

प्रकृति के संकेतों को समझने का वक्त

29 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में आसमान का अचानक गहरा लाल हो जाना केवल एक खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य नहीं था, बल्कि बदलते मौसम और पर्यावरणीय असंतुलन पर गंभीरता से विचार करने का अवसर भी था। चक्रवात अर्नब के प्रभाव के बीच दिखाई दिए इस असामान्य नजारे ने लोगों को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए। किसी ने इसे प्रकृति का चमत्कार कहा तो किसी ने आने वाले बड़े संकट का संकेत माना। हालांकि, इस लालिमा का सटीक वैज्ञानिक कारण अभी प्रमाणित नहीं हुआ है और इसे सीधे चक्रवात से जोड़ने की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी इस घटना ने एक जरूरी सवाल खड़ा किया है..



क्या हम प्रकृति के बदलते संकेतों को पर्याप्त गंभीरता से समझ रहे हैं?

विज्ञान के अनुसार, सूर्य की किरणें जब वायुमंडल से गुजरती हैं, तो धूल, धुआं, नमी और दूसरे सूक्ष्म कण प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रभावित करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में लंबा रास्ता तय करता है, जिससे लाल और नारंगी रंग अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। वातावरण में धूल और दूसरे कणों की अधिकता इस प्रभाव को और गहरा कर सकती है। किरंदुल जैसे लौह अयस्क खनन क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ धूल और मिट्टी के कणों का फैलना भी एक संभावित कारण हो सकता है। हालांकि, बिना वैज्ञानिक जांच के इस घटना को खनन गतिविधियों या चक्रवात का सीधा परिणाम बताना उचित नहीं होगा। इसके लिए स्थानीय मौसम, हवा की दिशा और वायुमंडलीय कणों का अध्ययन जरूरी है।

लेकिन चिंता केवल एक दिन आसमान के लाल दिखाई देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का बदलता मिजाज हमारी पर्यावरणीय तैयारियों की लगातार परीक्षा ले रहा है। कहीं कम समय में अत्यधिक बारिश से बाढ़ आ रही है, तो कहीं लंबे समय तक सूखे की स्थिति बनी रहती है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी, हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ तथा समुद्री तटों पर चक्रवातों का बढ़ता प्रभाव गंभीर चिंता का विषय है। इन घटनाओं का असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कृषि, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और आम जनजीवन पर भी पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन इस चुनौती का एक महत्वपूर्ण पहलू है। औद्योगीकरण, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ा रहे हैं। इससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। गर्म वातावरण अधिक नमी धारण कर सकता है, जिसके कारण अनुकूल परिस्थितियों में अत्यधिक बारिश की घटनाओं की तीव्रता बढ़ सकती है। समुद्र का बढ़ता तापमान भी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता और उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, हर असामान्य मौसमी घटना को केवल जलवायु परिवर्तन का परिणाम मानना वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं होगा।

इसके अलावा अल नीनो, ला नीना, हिंद महासागर द्विध्रुव और वायुमंडलीय परिसंचरण जैसे प्राकृतिक कारक भी भारत के मौसम को प्रभावित करते हैं। इनका असर मानसून, वर्षा के वितरण और चक्रवातों की गतिविधियों पर पड़ता है। इसलिए मौसम में होने वाले बदलावों को समझने के लिए दीर्घकालीन आंकड़ों और वैज्ञानिक अध्ययनों को आधार बनाना आवश्यक है।

इस पूरे परिदृश्य में मानवीय गतिविधियों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, जंगलों का कम होना, जलाशयों पर अतिक्रमण और खनन गतिविधियों का विस्तार स्थानीय पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर रहा है। विकास आवश्यक है, लेकिन ऐसा विकास जो प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की कीमत पर हो, भविष्य में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। विशेष रूप से खनन क्षेत्रों में धूल नियंत्रण, वायु गुणवत्ता की निगरानी और पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी केवल आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

DPDP कानून में पत्रकारिता को छूट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती लंबित

डिजिटल युग में किसी व्यक्ति की निजी जानकारी की सुरक्षा बेहद जरूरी हो गई है। बैंकिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन खरीदारी और सरकारी सेवाओं के विस्तार के साथ लोगों का व्यक्तिगत डेटा लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहा है। ऐसे में डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत कानून की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब डेटा सुरक्षा का यही कानून खोजी पत्रकारिता और जनता के जानने के अधिकार के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो जाए, तो इसके प्रावधानों पर गंभीर चर्चा जरूरी हो जाती है। भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून इसी बहस के केंद्र में है।



साल 2023 में संसद से पारित DPDP कानून का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना और उसके इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करना है। इसके तहत व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल, सहमति और उससे जुड़े अधिकारों के लिए नियम बनाए गए हैं। हालांकि, इस कानून में पत्रकारिता के लिए कोई स्पष्ट विशेष छूट नहीं दी गई है। यही बात मीडिया संस्थानों, पत्रकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े संगठनों की चिंता का कारण बनी हुई है।

खोजी पत्रकारिता का काम अक्सर ऐसी जानकारियां सामने लाना होता है, जिन्हें सार्वजनिक करने में संबंधित व्यक्ति या संस्था की सहमति मिलना मुश्किल होता है। भ्रष्टाचार, सरकारी अनियमितताओं, कॉरपोरेट गड़बड़ियों और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही से जुड़े मामलों में पत्रकारों को दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और व्यक्तिगत जानकारियों की पड़ताल करनी पड़ती है। यदि हर बार संबंधित व्यक्ति की सहमति लेना अनिवार्य हो जाए, तो कई महत्वपूर्ण जांच शुरू होने से पहले ही प्रभावित हो सकती हैं।

कानून में छूट का अभाव क्यों बना चिंता?

DPDP कानून की धारा 17 में कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट का प्रावधान है। इसमें शोध, अभिलेख संरक्षण और सांख्यिकीय उद्देश्यों जैसी गतिविधियां शामिल हैं, लेकिन पत्रकारिता को अलग श्रेणी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसका असर उन रिपोर्टों पर पड़ सकता है, जिनमें सार्वजनिक हित से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए बिना पूर्व सूचना के जांच करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई पत्रकार किसी सरकारी अधिकारी की संपत्ति, ठेकों में कथित अनियमितता या किसी कंपनी के वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहा है, तो संबंधित व्यक्ति को पहले सूचना देना जांच की गोपनीयता को प्रभावित कर सकता है। वहीं, डेटा हटाने या उसके इस्तेमाल पर आपत्ति से जुड़ी मांगें प्रकाशित खबरों और पत्रकारों के पास मौजूद दस्तावेजों को लेकर नए कानूनी सवाल खड़े कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा विवाद

इस मुद्दे पर 27 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। एसोसिएशन ने DPDP कानून और 2025 के नियमों को चुनौती देते हुए दलील दी है कि पत्रकारिता के लिए छूट नहीं होने से खोजी रिपोर्टिंग प्रभावित हो सकती है और गोपनीय सूत्रों की पहचान उजागर होने का खतरा बढ़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है और केंद्र का पक्ष सुनने की जरूरत बताई है। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को निर्धारित है। हालांकि, अदालत ने अभी कानून की संवैधानिक वैधता या पत्रकारिता को छूट देने के सवाल पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।

सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि DPDP कानून प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता और मीडिया के सुझावों पर विचार किया जा सकता है। सरकार और मीडिया संगठनों के बीच यही मतभेद अब न्यायिक परीक्षण का विषय है।

निजता और प्रेस की स्वतंत्रता में संतुलन जरूरी

यहां यह समझना जरूरी है कि निजता का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता एक-दूसरे के विरोधी अधिकार नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा देता है, जबकि अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लोकतंत्र में दोनों का अपना महत्व है। समस्या तब पैदा होती है, जब किसी एक अधिकार की रक्षा के लिए दूसरे अधिकार के इस्तेमाल पर अनावश्यक बाधाएं खड़ी होने लगती हैं। DPDP कानून के प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 से लागू होने निर्धारित हैं। इसलिए सरकार के पास अभी भी पत्रकारिता, संपादकीय कार्य और जनहित से जुड़ी जांच के लिए स्पष्ट और सीमित छूट की व्यवस्था पर विचार करने का अवसर है।

निष्कर्षत:, डेटा सुरक्षा कानून का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित करना होना चाहिए, न कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिनमें सार्वजनिक हित के सवाल उठाना मुश्किल हो जाए। पत्रकारिता को भी निजता के नाम पर किसी की निजी जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही से जुड़ी खोजी रिपोर्टिंग को भी पर्याप्त कानूनी संरक्षण मिलना जरूरी है।

इंडिया ITIB दैट इज भारत
साप्ताहिक समाचार पत्र

सेना को मिलेंगी स्वदेशी मिसाइल प्रणाली की 5–6 रेजिमेंट

BEL होगी मुख्य निर्माता, चित्रकूट में बन रहा उत्पादन केंद्र

वायु रक्षा को मज़बूती की तैयारी: 'अनंत शस्त्र' के ₹30,000 करोड़ के सौदे पर अंतिम मुहर का इंतज़ार

ITIB डेस्क

नई दिल्ली। भारतीय सेना अपनी वायु रक्षा को मज़बूत करने के लिए स्वदेशी 'अनंत शस्त्र' मिसाइल प्रणाली ख़रीदने की तैयारी में है। इसे पहले QRSAM, यानी क्विक रिएक्शन सरफ़ेस-टू-एयर मिसाइल, के नाम से जाना जाता था। करीब 30,000 करोड़ के इस सौदे के लिए सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को मुख्य निर्माता चुना गया है।

सौदा कहां तक पहुंचा?: सेना ने सितंबर 2025 में BEL को करीब 30,000 करोड़ का टेंडर जारी किया था। इसके तहत 'अनंत शस्त्र' की पांच से छह रेजिमेंट ख़रीदी जानी हैं। रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) इस ख़रीद को ज़रूरत की मंज़ूरी पहले ही दे चुकी है। रिपोर्टों के मुताबिक BEL अपनी ओर से सारी तैयारियां पूरी कर चुकी है। अब सौदे को सिर्फ़ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की अंतिम मंज़ूरी का इंतज़ार है। इसके बाद ही औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे।

सेना को क्यों ज़रूरत?: आधुनिक युद्ध में ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलें सबसे बड़ा ख़तरा बनकर उभरी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाव में वायु रक्षा प्रणालियों की अहमियत सामने आई थी।

जानकारों के मुताबिक 'अनंत शस्त्र' चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात टुकड़ियों के लिए अहम होगी। ये आगे बढ़ती बख़्तरबंद टुकड़ियों को हवाई हमलों से छतरी जैसी सुरक्षा देगी।



क्या है 'अनंत शस्त्र'?

'अनंत शस्त्र' को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है। ये कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। रक्षा मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक ये 5 से 30 किलोमीटर की दूरी और करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के हवाई ख़तरों को निशाना बना सकती है। ये लड़ाकू विमानों, हेलिकॉप्टरों, ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलों के ख़िलाफ़ काम आती है। मिसाइल ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर से चलती है, और आख़िरी चरण में अपने ही सीकर से निशाने को खोजकर उस पर वार करती है। एक बार में निशाना भेदने की इसकी संभावना 80% से ज़्यादा बताई गई है। इसकी सबसे बड़ी ख़ूबी रफ़्तार और गतिशीलता है। पूरी प्रणाली गाड़ियों पर लगी होती है, इसलिए ये सेना की टुकड़ियों के साथ चल सकती है। चलते-चलते ही ये अपने रडार से ख़तरे को खोज और ट्रैक कर सकती है।

चित्रकूट में बनेगी

सौदा पक्का होने पर इसका उत्पादन भी भारत में ही होगा। BEL को अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश डिफ़ेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में 75 हेक्टेयर ज़मीन मिली है। कंपनी वहां 600 करोड़ से ज़्यादा लगाकर नया उत्पादन केंद्र बना रही है। इस केंद्र में QRSAM के साथ लंबी दूरी की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली 'कुशा' और नई पीढ़ी के रडार भी बनेंगे। यहां इन प्रणालियों के रखरखाव और मरम्मत की सुविधा भी होगी।

BEL के लिए कितना बड़ा?: वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में BEL के पास करीब 73,900 करोड़ के ऑर्डर थे। जानकारों के मुताबिक ये सौदा पक्का होने पर कंपनी के ऑर्डर पहली बार 1 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएंगे।



DRDO का प्रलय मिसाइल परीक्षण सफल, भारतीय सेना की ताकत में होगा इजाफा

ITIB डेस्क

नई दिल्ली। भारत ने अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 5 नवंबर 2026 को ओडिशा तट के पास अपनी अत्याधुनिक क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण सुबह करीब 11:10 बजे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सभी निर्धारित मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों में इस मिसाइल को शामिल करने का रास्ता लगभग साफ हो गया है।

क्या है प्रलय मिसाइल की खासियत?: प्रलय भारत में विकसित कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 150 से 500 किलोमीटर तक बताई गई है। यह 500 से 1,000 किलोग्राम तक का पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें ठोस ईंधन (Solid Propellant) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी आधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन प्रणाली लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में मदद करती है। यह अलग-अलग प्रकार के लक्ष्यों के लिए विभिन्न श्रेणियों के वारहेड ले जा सकती है।

बैलिस्टिक मिसाइल से कैसे अलग है प्रलय?

प्रलय को क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह केवल एक निश्चित और अनुमानित रास्ते पर निर्भर नहीं रहती। इसकी उड़ान अपेक्षाकृत नीचे हो सकती है और यह रास्ते में अपनी दिशा बदलने तथा जरूरी पैंतरेबाजी करने में सक्षम है। इससे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसकी उड़ान का अनुमान लगाना और इसे रोकना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।



AI से हमला, AI से बचाव साइबर सुरक्षा की नई जंग

बाइनेंस चोरी के बाद कंपनियां AI आधारित निगरानी बढ़ा रहीं

त्योहारी सेल में करीब 2 लाख नकली ऑफ़र और वेबसाइटें मिलीं

ITIB डेस्क.नई दिल्ली। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) ने साइबर दुनिया में चोर-पुलिस के खेल को और तेज़ कर दिया है। एक तरफ़ ठग और हैकर AI की मदद से पहले से ज़्यादा भरोसेमंद जाल बिछा रहे हैं। दूसरी तरफ़ बैंक, कंपनियां और सुरक्षा एजेंसियां भी उन्हें पकड़ने के लिए AI का ही सहारा ले रही हैं।

इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी: इस बहस को 29 अक्टूबर की घटना ने और तेज़ कर दिया। उस दिन दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक, बाइनेंस, से करीब 6.3 अरब डॉलर की डिजिटल संपत्ति चुरा ली गई। इसे क्रिप्टो के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया जा रहा है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने इसके पीछे उत्तर कोरिया से



जुड़े एक हैकर समूह का हाथ बताया है। उत्तर कोरिया ने इन आरोपों को बेतुका बताकर ख़ारिज कर दिया।इस घटना के बाद दुनिया भर में वित्तीय कंपनियां अपनी सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा कर रही हैं।

त्योहार पर ठगों की 'सेल': भारत में ख़तरा घर के और करीब है। ऑनलाइन धोखाधड़ी पर नज़र रखने वाली कंपनी mFilterIt की 4 नवंबर को आई रिपोर्ट के मुताबिक इस त्योहारी सीज़न में करीब 2 लाख नकली ऑफ़र, हूबहू नकल की गई वेबसाइटें और फ़िशिंग लिंक पकड़े गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के 'साइबर दोस्त' ने भी अक्टूबर में चेतावनी दी थी कि ठग बड़े ब्रांडों के लोगो और सेल के डिज़ाइन वाले नकली विज्ञापन चला रहे हैं। इन पर क्लिक करते ही लोग असली जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं।

ठगों के हाथ में AI: जानकारों के मुताबिक AI ने ठगी को सस्ता, तेज़ और ज़्यादा भरोसेमंद बना दिया है। पहले फ़िशिंग ईमेल और मैसेज में भाषा की गलतियों से ठगी पहचान में आ जाती थी। अब AI बिना गलती के, किसी भी भाषा में, बिल्कुल असली जैसे संदेश लिख देता है।

इंडिया ITIB दैट इज भारत
साप्ताहिक समाचार पत्र

जयपुर, रविवार, 08 नवंबर 2026

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय: महिला और बाल सुरक्षा को मिलेगी मजबूती

ITIB डेस्क

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय की वास्तविक सफलता केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि पीड़ित को समय पर न्याय मिलने से तय होती है। विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध और बच्चों के शोषण से जुड़े मामलों में न्याय मिलने में होने वाली देरी पीड़ितों के लिए दोहरी पीड़ा का कारण बनती है।

इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO) से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSCs) की केंद्र प्रायोजित योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह विस्तार 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगा।

इस निर्णय का उद्देश्य केवल अदालतों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। विशेष न्यायालयों के माध्यम से मामलों का समयबद्ध निस्तारण होने पर पीड़ितों और उनके परिवारों का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हो सकता है।



लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल भी है। अदालतों की संख्या बढ़ाने के साथ पर्याप्त न्यायाधीशों, अभियोजन अधिकारियों, कर्मचारियों और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। न्याय में तेजी का अर्थ केवल मुकदमों का निपटारा करना नहीं, बल्कि निष्पक्ष सुनवाई और गुणवत्तापूर्ण न्याय सुनिश्चित करना भी है। इस दिशा में प्रभावी क्रियान्वयन ही इस योजना की वास्तविक सफलता तय करेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के ये चारों फैसले अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े होने के बावजूद भारत के भविष्य की चार महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को रेखांकित करते हैं। ऊर्जा भंडारण देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, महत्वपूर्ण खनिजों का घरेलू प्रसंस्करण औद्योगिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, VISTAR योजना नीति निर्माण को आंकड़ों और तकनीक से जोड़ेगी तथा फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम करेंगे।

इन फैसलों को केवल करोड़ों रुपये के बजटीय प्रावधान के रूप में देखना उचित नहीं होगा। वास्तव में ये आने वाले पांच वर्षों के लिए देश की आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक प्राथमिकताओं का संकेत देते हैं। इनका प्रभाव उद्योगों से लेकर आम नागरिकों और न्याय व्यवस्था तक दिखाई दे सकता है।

फिर भी किसी भी योजना की सफलता उसकी घोषणा या स्वीकृत बजट से नहीं, बल्कि उसके परिणामों से मापी जाती है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं कितनी तेजी से पूरी होती हैं, खनिज प्रसंस्करण में भारत कितना आत्मनिर्भर बनता है, सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता कितनी बढ़ती है और महिलाओं एवं बच्चों को न्याय कितनी जल्दी मिल पाता है। अंततः, इन चार फैसलों की असली परीक्षा अगले पांच वर्षों में होगी। यदि सरकार इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल रहती है, तो ये फैसले विकसित भारत के लक्ष्य को केवल राजनीतिक संकल्प नहीं, बल्कि जमीनी वास्तविकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ईरान की शर्त: नाकाबंदी हटे, प्रतिबंधों में राहत मिले; ईरान से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में भारतीय कंपनियां भी

250 दिन बाद भी ईरान युद्ध जारी... शांति की उम्मीद से तेल 18% टूटा

ITIB डेस्क. नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच इस साल शुरू हुए युद्ध को 5 नवंबर को करीब 250 दिन पूरे हो गए। एक तरफ़ हमले जारी हैं, दूसरी तरफ़ बिचौलियों के ज़रिए समझौते की कोशिशें भी तेज़ हुई हैं। इसी उम्मीद में इस हफ़्ते अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल 18% से ज्यादा सस्ता हो गया।

हमले और बातचीत साथ-साथ

अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक 2 नवंबर को, मिडटर्म चुनाव से ठीक पहले, अमेरिकी सेना ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास ईरानी ठिकानों पर सीमित हमले किए। ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके बाद कहा कि वे दोबारा बड़े हमले शुरू करने को लेकर निश्चित नहीं हैं, और ईरान से समझौता हो सकता है। क़तर और पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

होर्मुज़ क्यों अहम?

होर्मुज़ फ़ारस की खाड़ी का संकरा समुद्री रास्ता है, जिससे दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुज़रता है। यहां ज़रा-सी हलचल भी दुनिया भर में तेल के दाम हिला देती है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि वहां से गुज़रने की कोशिश कर रहे चार जहाज़ बारूदी सुरंगों से टकराए। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।



ईरान की शर्तें

ईरान ने साफ़ कहा है कि उसकी मांगें पूरी होने तक होर्मुज़ नहीं खुलेगा। उसकी मुख्य शर्तें हैं:

- ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकाबंदी ख़त्म हो
- तेल पर लगे प्रतिबंधों में राहत मिले
- विदेशों में जमी ईरान की रकम लौटाई जाए

ईरान का कहना है कि इन शर्तों के बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी। अमेरिका ने अब तक इन पर कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया है। सीधी बातचीत की कोई तारीख़ भी तय नहीं है।

क्रिप्टो बाज़ार धड़ाम: बिटकॉइन 6% टूटकर 75,000 डॉलर के पास



टेक शेयरों की बिकवाली का असर; 24 घंटे में करीब 1 अरब डॉलर के सौदे लिक्विडेट, बाज़ार से करीब 140–150 अरब डॉलर साफ़

ITIB डेस्क.नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 5 और 6 नवंबर को करीब 6% गिरकर 75,000 डॉलर के पास आ गई। हफ़्ते की शुरुआत में ये 80,000 डॉलर से ऊपर कारोबार कर रही थी। ये सितंबर के मध्य के बाद बिटकॉइन का सबसे निचला स्तर है। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ईथर भी 2,300 डॉलर से नीचे फिसल गई। कुछ ही घंटों में पूरे क्रिप्टो बाज़ार की कीमत से करीब 140 से 150 अरब डॉलर साफ़ हो गए।

गिरावट की शुरुआत: टेक शेयर: अमेरिका में चिप और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली हुई। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो बाज़ार अक्सर टेक शेयरों के साथ ही चढ़ता-गिरता रहा है, इसलिए ये असर तुरंत यहां भी दिखा।

लिक्विडेशन ने बढ़ाई गिरावट

बहुत से कारोबारी उधार लेकर बिटकॉइन के और चढ़ने का दांव लगा रहे थे। ऐसे सौदों में दाम एक तय सीमा से नीचे जाते ही सौदा अपने-आप कट जाता है। बाज़ार की भाषा में इसे लिक्विडेशन कहते हैं। 24 घंटे में करीब 1 अरब डॉलर के ऐसे सौदे कटे, जिनमें से लगभग 90% तेज़ी के दांव थे। एक घंटे के भीतर ही करीब 37 करोड़ डॉलर के सौदे ख़त्म हो गए। जब इतने सौदे एक साथ कटते हैं तो बिकवाली का दबाव और बढ़ता है, और गिरावट तेज़ हो जाती है।

भरोसे पर पहले से चोट

बाज़ार पहले से दबाव में था। 29 अक्टूबर को दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक, बाइनेंस, से करीब 6.3 अरब डॉलर की चोरी हुई। इसे इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी बताया जा रहा है।

अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने इसके लिए उत्तर कोरिया से जुड़े हैकर समूह को ज़िम्मेदार ठहराया। उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने इन आरोपों को "बेतुका" बताकर ठुकरा दिया। बाइनेंस का कहना है कि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है।

इंडिया ITIB दैट इज भारत
साप्ताहिक समाचार पत्र

पेज 1 का शेष...

PM मोदी-राहुल के बीच...

संसद में होने वाली बहस संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है, जबकि सार्वजनिक डिबेट में दोनों पक्षों को एक ही मंच पर अपने दावों, नीतियों और फैसलों का जवाब देना होता है। राहुल गांधी की चुनौती और BJP के जवाब ने इस बहस को फिर से सामने ला दिया है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच बहस के मंच को लेकर मतभेद बना हुआ है। एक ओर विपक्ष सार्वजनिक मंच पर आमने-सामने की बहस की मांग कर रहा है, वहीं सरकार संसद के भीतर चर्चा को प्राथमिकता दे रही है। भारतीय लोकतंत्र में दोनों मंचों की अपनी भूमिका है। सार्वजनिक बहस की परंपरा विकसित होती है या नहीं, यह भविष्य की राजनीति पर निर्भर करेगा। लेकिन राजनीतिक जवाबदेही और मुद्दों पर तथ्य आधारित संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से बने रहेंगे।

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट...

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की, ''उम्मीद है आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे।'' उन्होंने कहा कि लगातार चर्चा और सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन AQI पहले ही 400 के करीब पहुंच चुका है। कोर्ट ने दिल्ली को गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद से जोड़ने वाली सड़कों पर वाहनों की भारी आवाजाही को भी प्रदूषण का बड़ा कारण बताया। **GRAP के बावजूद प्रदूषण पर नियंत्रण की चुनौतीः** दिल्ली-NCR में 2 नवंबर से GRAP का दूसरा चरण लागू किया गया था। इसके तहत सड़कों की सफाई, पानी का छिड़काव, पार्किंग शुल्क बढ़ाने और डीजल जनरेटर पर सख्ती जैसे कदम शामिल हैं। हालांकि, 6 नवंबर को वायु गुणवत्ता बिगड़ने के बाद CAQM ने GRAP का तीसरा चरण भी लागू कर दिया। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई, PUC प्रमाणपत्रों की जियो-टैगिंग और औद्योगिक उत्सर्जन तथा निर्माण की धूल पर नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं। **16 नवंबर को अगली सुनवाईः** सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल, मध्यम और दीर्घकालिक उपायों की जरूरत बताई। कोर्ट ने स्कूलों को बंद करने या हाइब्रिड कक्षाएं चलाने की मांग पर विशेषज्ञों की राय लेने की बात भी कही। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। साफ है कि दिल्ली की हवा सुधारने के लिए केवल पराली पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। वाहनों, सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक उत्सर्जन पर भी प्रभावी नियंत्रण जरूरी है।

भजनलाल सरकार के तीन ...

इसके अलावा यमुना जल समझौते और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 पर भी काम हो रहा है। जल स्वावलंबन अभियान के तहत अप्रैल 2026 तक 8 हजार से अधिक कार्य पूरे किए जाने की जानकारी सरकार ने दी थी।

सड़क, ऊर्जा और सामाजिक योजनाओं पर जोरः सरकार के अनुसार, उसके कार्यकाल में 51,790 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है, जिस पर 37,527 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए हैं। ऊर्जा क्षेत्र में सौर परियोजनाओं और बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सामाजिक योजनाओं में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, 450 रुपये में गैस सिलेंडर और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 1.50 लाख रुपये की सहायता प्रमुख हैं।

अगले दो साल की बड़ी चुनौतियांः उपलब्धियों के साथ सरकार के सामने रोजगार सबसे बड़ी चुनौती है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, राज्य की बेरोजगारी दर 4.2% है। सरकार की रोजगार नीति 2026 में मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केवल सरकारी भर्तियां नहीं, बल्कि निजी निवेश को रोजगार में बदलना भी जरूरी होगा। दूसरी चुनौती जल परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है। रामजल सेतु जैसी परियोजनाओं में अभी कई निर्माण कार्य जारी हैं। तीसरी चुनौती राज्य की वित्तीय स्थिति है। PRS के अनुसार, 2026-27 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.7% रहने का अनुमान है, जबकि बकाया कर्ज और ब्याज भुगतान विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों पर दबाव डालते हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की आय, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार भी सरकार के सामने अहम मुद्दे हैं।

घोषणाओं से नतीजों तक का सफरः भजनलाल सरकार के शुरुआती तीन साल निवेश आकर्षित करने, बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट शुरू करने और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के लिए उल्लेखनीय रहे हैं। लेकिन किसी भी सरकार के कामकाज का वास्तविक आकलन केवल बजट, समझौतों और घोषणाओं से नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में आए बदलाव से होता है। आने वाले दो साल तय करेंगे कि राजस्थान में घोषित निवेश कितनी नौकरियां पैदा करता है, पानी कितने घरों तक पहुंचता है और विकास का लाभ शहरों के साथ गांवों तक कितना पहुंचता है।

जनता की गाड़ी से हो रही पेट्रोल चोरी...

कंपनियों ने स्पष्ट किया कि E20 पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 19% से 21% के बीच होनी चाहिए। उन्होंने नमूने एकत्र करने और उनकी जांच की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई।

क्या है E20 पेट्रोल?: E20 पेट्रोल में 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। सरकार का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा बचाना और किसानों की आय बढ़ाना है। हालांकि, निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलने के आरोपों ने ईंधन की गुणवत्ता और वाहन चालकों के हितों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कैबिनेट के चार बड़े फ़ैसले, असर अगले पांच साल तक



ITIB डेस्क

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक आत्मनिर्भरता, सांख्यिकीय व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में चार बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 4 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सभी योजनाएं अगले पांच वर्षों की अवधि को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। इनमें ऊर्जा भंडारण के लिए 14,500 करोड़ रुपये और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए 2,814 करोड़ रुपये की सहायता प्रमुख है।

ऊर्जा भंडारण के लिए 14,500 करोड़ की योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 92 गीगावाट-घंटे (GWh) की ग्रिड स्तरीय ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए 14,500 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 30 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, 60 GWh पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं और 2 GWh उभरती हुई ऊर्जा भंडारण तकनीकों को विकसित किया जाएगा। योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य सौर एवं पवन ऊर्जा के बेहतर उपयोग, बिजली आपूर्ति में स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

लिथियम और निकेल के प्रसंस्करण के लिए 2,814 करोड़

सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत लिथियम और निकेल के प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी देने का प्रावधान है। योजना पांच वर्षों यानी 2026-27 से 2030-31 तक लागू होगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरण उद्योगों के लिए आवश्यक खनिजों की घरेलू प्रसंस्करण क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी।

VISTAR योजना के लिए 4,371.10 करोड़ रुपये मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च' (VISTAR) योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 4,371.10 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक संचालित होगी। इसके अंतर्गत देश की सांख्यिकीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण, सर्वेक्षणों की गुणवत्ता में सुधार, आंकड़ों के संग्रह एवं विश्लेषण में आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग तथा राज्यों की सांख्यिकीय क्षमता को मजबूत किया जाएगा। योजना के तहत आठवीं आर्थिक गणना और विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों को भी शामिल किया गया है।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की योजना पांच साल बढ़ाई

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक रहेगी। इसके लिए 3,788 .04 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। योजना के तहत विशेष अदालतों की संख्या मौजूदा 779 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है। इनमें बलात्कार और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य पीड़ितों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाना है।

चारों फैसलों का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में देश की क्षमता को मजबूत करना है। ऊर्जा क्षेत्र में भंडारण क्षमता बढ़ाने, महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण में घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने, सरकारी आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने और महिलाओं एवं बच्चों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने पर इन निर्णयों का विशेष जोर है।

अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव

अब 4 नहीं, 6 साल तक सेवा कर सकेंगे अग्निवीर, जानिए क्या होंगे नए नियम

ITIB डेस्क. नई दिल्ली। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए सेवा अवधि बढ़ाने की बात सामने आई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने 4 नवंबर 2026 को कहा कि अग्निवीरों को चार साल की सेवा पूरी होने के बाद दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जाएगा। इससे उन्हें अधिकतम छह साल तक सेना में सेवा करने का अवसर मिल सकेगा। इस बदलाव का उद्देश्य अग्निवीरों को अधिक समय तक सैन्य अनुभव हासिल करने का मौका देना है।

चार साल बाद मिलेंगे दो विकल्पः मौजूदा व्यवस्था के तहत चार साल की सेवा पूरी होने पर अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल किया जा सकता है। इनका चयन योग्यता, प्रदर्शन और सेना की जरूरतों के आधार पर होता है। वहीं, बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेवामुक्त किया जाता है। प्रस्तावित व्यवस्था में इन युवाओं को दो साल के अतिरिक्त कार्यकाल का विकल्प मिलेगा। नियमित कैडर में चुने गए अग्निवीरों को नियुक्ति के बाद शादी की अनुमति होगी।



क्या है अग्निपथ योजना?

केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की थी। इसके तहत 17 .5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को थल सेना, नौसेना और वायु सेना में चार साल के लिए भर्ती किया जाता है। भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। चार साल की सेवा पूरी होने पर उन्हें लगभग 11 .71 लाख रुपये की सेवा निधि दी जाती है। नियमित सैनिकों की तरह पेंशन का लाभ नहीं मिलता।

नियमित कैडर में शामिल होने का भी विकल्पः अतिरिक्त दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल होने का अवसर भी मिल सकेगा। हालांकि, इसके लिए निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया और सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। नियमित कैडर में चयनित अग्निवीर आगे निर्धारित सेवा नियमों के तहत काम करेंगे। इस बदलाव से सेना को अनुभवी जवान मिल सकेंगे, वहीं युवाओं को सैन्य करियर में आगे बढ़ने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

योजना के फायदे और चुनौतियांः योजना के समर्थकों का मानना है कि इससे सेना की औसत उम्र कम होगी और जवानों को आधुनिक तकनीक के अनुरूप तैयार किया जा सकेगा। युवाओं को कम उम्र में देश सेवा का अवसर मिलेगा। और सेवा निधि से वे आगे की पढ़ाई या रोजगार शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा, पेंशन पर होने वाला खर्च घटने से रक्षा बजट का इस्तेमाल आधुनिकीकरण में किया जा सकेगा।

इंडिया दैट इज भारत
ITIB
साप्ताहिक समाचार पत्र

NVS-03 अपनी कक्षा में स्थापित
NavIC की वापसी का रास्ता खुला

ITIB डेस्क

नई दिल्ली। भारत ने अपनी स्वदेशी अंतरिक्ष और नेविगेशन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 30 अक्टूबर 2026 को नेविगेशन उपग्रह NVS-03 का सफल प्रक्षेपण किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F18 रॉकेट के जरिए रात 11:51 बजे उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। यह GSLV की 20वीं उड़ान थी। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद NVS-03 को सफलतापूर्वक भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) में स्थापित कर दिया गया।

इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली NavIC को फिर से मजबूत करना है। NVS-03 के कक्षीय संचालन और आवश्यक परीक्षण पूरे होने के बाद परिचालन उपग्रहों की संख्या तीन से बढ़कर चार हो सकती है। इससे NavIC के संचालन के लिए जरूरी न्यूनतम संख्या पूरी करने में मदद मिलेगी। यह भारत की रणनीतिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण कदम है।

क्या है NavIC और कैसे करता है काम?: NavIC यानी Navigation with Indian Constellation भारत की अपनी क्षेत्रीय उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। इसे ISRO ने विकसित किया है। पहले इसे भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और आसपास के क्षेत्रों में सटीक लोकेशन, नेविगेशन और समय संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना है।



NVS-03 क्यों है महत्वपूर्ण?

NVS-03 के आने से NavIC की परिचालन क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस प्रणाली के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों को सुरक्षित और विश्वसनीय नेविगेशन सिग्नल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सीमा सुरक्षा, सैन्य वाहनों की आवाजाही और रणनीतिक अभियानों में सटीक लोकेशन की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन, मछुआरों, परिवहन सेवाओं और आपदा प्रबंधन के लिए भी यह उपयोगी साबित हो सकता है।

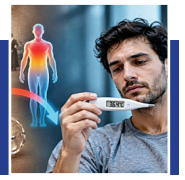
NavIC का प्राथमिक सेवा क्षेत्र भारत और इसकी सीमाओं से लगभग 1,500 किलोमीटर तक फैला है। इसका विस्तारित सेवा क्षेत्र इससे भी आगे तक पहुंचता है। इस प्रणाली का इस्तेमाल परिवहन, समुद्री नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, सर्वेक्षण और सैन्य गतिविधियों में किया जा सकता है।

दुनिया की प्रमुख नेविगेशन प्रणालियां: उपग्रह आधारित नेविगेशन के क्षेत्र में दुनिया के कुछ प्रमुख देशों और संगठनों की अपनी प्रणालियां हैं। अमेरिका का GPS, रूस का GLONASS, यूरोपीय संघ का Galileo और चीन का BeiDou वैश्विक नेविगेशन प्रणाली हैं। वहीं भारत का NavIC और जापान का QZSS क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणालियां हैं।

आज के दौर में नेविगेशन तकनीक केवल मोबाइल फोन में लोकेशन बताने तक सीमित नहीं है। यह रक्षा, अर्थव्यवस्था, संचार, परिवहन और राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। ऐसे में NVS-03 का सफल प्रक्षेपण भारत को विदेशी नेविगेशन प्रणालियों पर निर्भरता कम करने और अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए स्वतंत्र तकनीकी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाता है।



नई रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा... पहले के मुकाबले आज इंसानों का औसत बॉडी टेम्परेचर कम



150 साल में बदला शरीर के सामान्य तापमान का पैमाना

ITIB डेस्क

हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि इंसान के शरीर का सामान्य तापमान 37°C यानी 98.6°F होता है। लेकिन अब वैज्ञानिक शोध इस स्थापित मान्यता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले करीब 150 वर्षों में इंसानों के औसत शरीर के तापमान में लगातार गिरावट देखी गई है।

1860 में तय हुआ था 98.6°F का मानक: शरीर के सामान्य तापमान का यह पैमाना जर्मन डॉक्टर कार्ल वुंडरलिच ने 19वीं सदी में हजारों मरीजों के तापमान का अध्ययन करने के बाद तय किया था। तब से इसे सामान्य बॉडी टेम्परेचर का मानक माना जाता रहा है।

स्टैनफोर्ड की रिसर्च ने खोला राज: 2020 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 1860 के दशक से 2017 तक के करीब 6.77 लाख तापमान रिकॉर्ड का विश्लेषण किया। इसमें सामने आया कि आज की पीढ़ी का औसत शरीर का तापमान पहले के मुकाबले कम है।

भारत के तीन स्वदेशी AI मॉडल लॉन्च, दो बिना इंटरनेट भी करेंगे काम

ITIB डेस्क

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत एआई मिशन के तहत 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में तीन स्वदेशी आधारभूत एआई मॉडल पेश किए गए। इनमें ईका-1 (Eka-1) और धीर (Dhir) के दो मॉडल 2B और 5B शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में एआई की पहुंच बढ़ाना और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सुरक्षित तकनीकी समाधान विकसित करना है। इन मॉडलों की खास बात यह है कि इनमें से दो को बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी स्थानीय डिवाइस पर चलाया जा सकता है।



भारत के AI मिशन को मिलेगी मजबूती

भारत में एआई का उपयोग तेजी से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग और उद्योग जैसे क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ऐसे में स्वदेशी मॉडल विकसित करना केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं को एआई के सही इस्तेमाल, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं।

ईका-1: 22 भारतीय भाषाओं में करेगा काम: सोकेट लैब्स टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च द्वारा विकसित ईका-1 संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी को सपोर्ट करता है। इसे बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसकी विशेषता यह है कि कुछ कार्यों के लिए यह स्मार्टफोन जैसे स्थानीय उपकरणों पर ही गणना कर सकता है। इससे हर बार इंटरनेट या क्लाउड सर्वर से जुड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों और डेटा गोपनीयता को प्राथमिकता देने वाले संस्थानों के लिए यह उपयोगी साबित हो सकता है।

धीर 2B और 5B: डेटा सुरक्षा पर जोर: धीर के 2B और 5B मॉडल को संवेदनशील संस्थानों और कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। ये मुक्त-स्रोत मॉडल अंग्रेजी सहित 10 भारतीय भाषाओं में काम कर सकते हैं। इन्हें किसी संस्था के अपने कंप्यूटर सिस्टम या सर्वर पर स्थापित किया जा सकता है। इनकी मदद से दस्तावेजों में जानकारी खोजना, सवालों के जवाब तैयार करना और कई नियमित कार्यों को स्वचालित करना संभव होगा।

इन मॉडलों की स्थानीय तैनाती का सबसे बड़ा फायदा डेटा सुरक्षा है। सामान्य क्लाउड आधारित एआई सेवाओं में जानकारी बाहरी सर्वर तक पहुंच सकती है, जबकि स्थानीय स्तर पर चलने वाले मॉडल संवेदनशील डेटा को संस्थान के अपने सिस्टम में सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक अंकित कुमार अवस्थी के लिए स्काईटेक प्रिन्टर्स, 111 नवाब कल्लन का बाग, एम आई रोड़ से मुद्रित होकर, प्लाट नंबर 53 महादेव नगर, जयपुर से प्रकाशित।
*प्रधान संपादक अंकित कुमार अवस्थी (समाचार चयन के लिए पी आर पी एक्ट के तहत जिम्मेदार) RNI NO RAJHIN26/A8486